



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1501]
No. 1501]नई दिल्ली, शुक्रवार, 24, 2008/कार्तिक 2 1930
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930मास और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2523(आ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (इ) के उप-खण्ड (vi) के उपर्योग के अनुसरण में भारत सरकार के त्राम और रोजगार पंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. दिनांक 2-5-2008 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल) जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रतिचिह्न 25 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 2-5-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की याच है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (इ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उपयोग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 2-11-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96-आई.आर.(पी.एल.)]

एस. कृष्णन, विशेष सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2008

S.O. 2523(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 2-5-2008 the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal) which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 2nd May, 2008;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 2nd November, 2008.

[F. No. S-11017/2/96-I.R.(PL)]

S. KRISHNAN, Spl. Secy.